समृद्धि की कोशिशें : क्यों वादों तक सिमट कर रह जाते हैं सरकारों के प्रयास

आखिर क्यों हैं हम गरीब

भारत एक गरीब देश है। पिछले 60-65 सालों से हम यह वाक्य सुनते आ रहे हैं। इस गरीबी को हटाने के नाम पर देश में क्या कुछ नहीं किया गया। सरकारें बदलीं, गरीबी हटाने के नारे और मुहावरे भी बदले। पर गरीबी नहीं हटी। गरीबी हटाने का अब तक हमारा अनुभव यही कहता है कि गरीबी हटाने और संपन्नता लाने के लिए किसी एक नेता या समूह या सरकार पर निर्भर रहने से हमें सफलता नहीं मिल सकती। संपन्नता किसी को सौंपी जा सकने वाली चीज नहीं है, यह तो लोगों के सामूहिक प्रयास से ही आती है। इसके लिए शैक्षिक डिग्रियां भी कई बार उपयोगी नहीं होतीं। संपन्नता के मार्ग पर सबसे अहम कोई चीज अगर है तो वह है प्रतिबंधों का न्यूनता। पढ़िए संपन्नता की खोज में भारत के अनुभव, जानकारों की राय में।

अमित चंद्रा, राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी

भारत गरीब क्यों है? यह संभवतः वह प्रश्न है जो न सिर्फ हमारे नीति निर्धारकों के बीच सर्वाधिक बहस और विमर्श का विषय रहा है वरन् सामान्य नागरिकों के बीच भी इस मुद्दे पर भारी चर्चा और विवाद होता रहा है। इसके बावजूद भी शायद हम आज तक देश में लंबे समय से व्याप्त गरीबी के मूल कारण को रेखांकित नहीं कर पाए हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में गरीबी उन्मूलन के अब तक अनेकों प्रयास किए गए पर आज भी देश में गरीबी की समस्या लगभग वैसी ही बनी हुई जैसी आरंभ में थी। यह विडंबना ही है कि 'गरीबी हटाओ' अभियान के तीन दशक बाद भी भारत की लगभग एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। विश्व बैंक के 2012 के आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 33 प्रतिशत आबादी सवा डॉलर प्रतिदिन से कम आय श्रेणी में आती है। यद्यपि गरीबी में रहने वाली आबादी के आंकड़ों और पैमानों पर बहस की जा सकती है और योजना आयोग के उन दावों का मजाक भी खूब बनाया जा सकता है जो यह बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 28 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाले लोग गरीब नहीं हैं।

> कई विश्लेषणों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि किसी देश की संपन्नता के लिए अन्य किसी भी कारक की तुलना में 'आर्थिक आजादी' का कारक सबसे निर्णायक होता है।

मूल सवाल की और लौटने के लिए प्रेरित करता है कि सबसे पहले हमें गरीबी के बारे में ही अनेकों भ्रामक धारणाओं, मिथकों पर पुनर्विचार की जरूरत है। गरीबी हटाने की हमारी कोशिशों की विफलताओं के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने समस्या की जड़ को ही कभी ठीक से समझा ही नहीं। इसीलिए अब तक हमने समस्या के जितने भी हल निकालने की कोशिश की है वे कमोबेश विफल ही रहे हैं।

खरे नहीं पुराने तर्क

सामान्यतः, गरीबी को तेजी से बढ़ती आबादी के परिणाम के रूप में देखा जाता है। प्रथम दृष्ट्या यह सही भी लगता है, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि उतनी तेज नहीं रही है जितनी कि आबादी में। भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर भारत के सामने उपस्थित बड़ी समस्याओं पर चर्चा के लिए भारतीय संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें आबादी की समस्या सबसे शीर्ष पर रही। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण था जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने, संसद में बैठकर, यह तय किया कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में जनता ही है। इसी प्रकार से संजय गांधी भी बाध्यकारी नसबंदी के माध्यम से जनता को 'नियंत्रित' करना चाहते थे। पर, अगर आबादी ही गरीबी का मूल कारण होती तो अधिक आबादी घनत्व वाले सभी देश भी गरीब होते। ऐसा है नहीं। भारत का आबादी घनत्व 416 तथा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 5138 डॉलर है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनका आबादी घनत्व भारत से अधिक है इसके बावजूद उनका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भारत से अधिक है। जैसे नीदरलैंड और हांगकांग। दोनों का आबादी घनत्व क्रमशः 497 तथा

अगर ऐसा होता तो 94 प्रतिशत साक्षरता के साथ केरल 77 प्रतिशत साक्षरता वाले हरियाणा की तुलना में संपन्न नजर आता। पर हकीकत में केरल और हरियाणा का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्रमशः 53,430 तथा 63,050 रुपये है। हमारे आसपड़ोस में भी सबसे शिक्षित व्यक्ति सबसे संपन्न देखने में नहीं आता। गरीबी के अन्य दूसरे समझे जाने वाले कारण हैं औपनिवेशिक अतीत, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, नीतियां तथा परलोकोन्मुखी रुझान। पर आंकड़ों से इसकी पुष्टि नहीं होती। उदाहरण के लिए भारत से देर तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हांगकांग आज प्रति व्यक्ति 51, 170 डॉलर जीडपी के साथ ब्रिटेन (जीडीपी 39, 351 डॉलर प्रति व्यक्ति) को भी पीछे छोड़ चुका है।

गहराई से देखें तो गरीबी के कारणों की व्याख्या करने वाले उपरोक्त सभी कारकों का गरीबी से कुछ न कुछ संबंध तो है पर इनका

दो प्रणालियां, दो परिणाम

पूरे मसले की बेहतर समझ के लिए हम उन देशों का उदाहरण ले सकते हैं जो कि किन्हीं कारणवश दो भागों में बांट दिए गए जैसे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, पूर्व जर्मनी और पश्चिमी। 1950 में विभाजन के समय कोरिया का सकल घरेलू उत्पाद 854 डॉलर था। वहीं 2010 में दक्षिण कोरिया का प्रति व्यक्ति जीडीपी जहां 19614 डॉलर तक पहुंच गया तो उत्तर कोरिया के जीडीपी (1122) में इन 60-65 वर्षों में बहुम मामूली वृद्धि दर्ज की गई। यही कहानी पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी की भी है।

जब हम किसी देश में आर्थिक आजादी की स्थिति और उस देश में संपन्नता के हालात पर नजर डालते हैं तो आंकड़े आर्थिक आजादी और बेहतर जीडीपी के समानुपाती संबंध की कहानी कहते हैं। आंकड़े यह भी कहते हैं कि जितने जल्दी कोई देश

अमर्त्य सेन की चिंता

अमर्त्य सेन समेत कई विशेषज्ञ यह तर्क देते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश किए बिना कोई भी देश तेज आर्थिक संपन्नता की सीढ़ी नही चढ़ सकता। सरकारों को सबसे पहले साक्षरता और स्वास्थ्य सूचकांकों जैसे पोषण और शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों को सुधारना चाहिए, इसी के बाद कोई देश आर्थिक समृद्धि के राजमार्ग पर बढ़ सकता है। पर खुद भारत का अनुभव ही आर्थिक आजादी की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है।

1991 में आर्थिक उदारीकरण और औद्योगिक लाइसेंस से छूट आदि के बाद भारत में कम से कम संगठित क्षेत्र में आर्थिक आजादी के हालात में काफी सुधार दर्ज किया गया है। परिणामस्वरूप , इस बीच साक्षरता और स्वास्थ्य के हालात में कोई विशेष सुधार दर्ज किए बिना भारत ने पिछले दशकों की 3-4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में 7 से 9 प्रतिशत की

पर यह सवाल अपनी जगह कायम है कि सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सतत प्रयासों के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में लोग आज भी क्यों गरीबी में रहने को मजबूर हैं? क्या लोग गरीबी से बाहर नहीं आना चाहते या फिर वे पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं अथवा लोगों द्वारा किए गए प्रयासों के अनुकूल समुचित अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं या फिर हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं? यह सब हमें इस

8866 और प्रति व्यक्ति जीडीपी 43,339 तथा 51, 170 है। इसी तरह ऐसे देश भी हैं जिनका आबादी घनत्व भारत से कम है फिर भी भारत से गरीब हैं, जैसे मोजांबिक, तंजानिया आदि।

गरीबी के लिए जिम्मेदार दूसरा कारण अशिक्षा को भी समझा जाता है। पर यहां भी अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो गरीबी और अशिक्षा में समानुपातिक संबंध नजर नहीं आता।

गरीबी से कोई सीधा समानुपातिक संबंध स्थापित नहीं होता है। हकीकत में गरीबी निवारण के जितने भी कार्यक्रम अब तक चलाए गए हैं वे अच्छी राजनीति तो जरूरत साबित हुए हैं पर अच्छी अर्थनीति नहीं। अच्छी अर्थनीति वह है जहां संस्थाओं और नीतियों की वृहत्तर रूपरेखा आम नागरिक के लिए आर्थिक आजादी को सीमित करने के बजाए उसका विस्तार करती है।

आर्थिक आजादी सूचकांक पर सुधार दर्ज करता है उतना ही तेज वृद्धि दर वह देश दर्ज करता है। 2013 की आर्थिक आजादी रिपोर्ट में हांगकांड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विटजरलैंड और यूएई शीर्ष पर हैं और यही देश प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में भी शीर्ष देश हैं। भारत आर्थिक आजादी के पैमाने पर दुनिया के 152 देशों में 111वें स्थान पर है, जो कि चीन से भी नीचे है।

वृद्धि दर दर्ज की है। आर्थिक सुधारों के 20 साल बाद भारत आज आबादी विशेषकर युवाओं को अपनी ताकत बना चुका है। दो दशकों में आय 300 डॉलर प्रति व्यक्ति से बढ़कर 1700 डॉलर तक पहुंच चुकी है। इस विकास दर से मिले राजस्व के कारण ही आज भारत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गारंटी जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर रिकॉर्ड राशि खर्च करने की स्थिति में आ सका है।